



राजपत्र, हिमाचल प्रदेश (असाधारण)

हिमाचल प्रदेश राज्य शासन द्वारा प्रकाशित

शिमला, मंगलवार, १७ मार्च, १९९८/२६ फाल्गुन, १९१९

हिमाचल प्रदेश सरकार

लोक निर्माण विभाग

अधिसूचनाएं

शिमला-२; ९ फरवरी, १९९८

संख्या लो० नि० (ख) ७(१)२४५/९७.—यतः हिमाचल प्रदेश के राज्यपाल को यह प्रतीत होता है कि हिमाचल प्रदेश सरकार को सरकारी व्यय पर सार्वजनिक प्रयोजन हेतु नामतः गांव भुवाना, तहसील घुमरवी, जिला बिलासपुर में बाड़ा दा घाट भूपराल कुठेड़ा सड़क के निर्माण हेतु भूमि अर्जित करनी अपेक्षित है, अतएव एतद्वारा यह अधिसूचित किया जाता है कि उक्त परिक्षेत्र में जैसा कि निम्न विवरणी में निर्दिष्ट किया गया है, उपरोक्त प्रयोजन के लिए भूमि का अर्जन अपेक्षित है।

२. यह अधिसूचना ऐसे सभी व्यक्तियों को जो इससे सम्बन्धित हो सकते हैं, की जानकारी के लिए भूमि अर्जन अधिनियम, १८९४ की धारा-४ के उपबन्धों के अन्तर्गत जारी की जाती है।

3. पूर्वोक्त धारा द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए राज्यपाल, हिमाचल प्रदेश इस उपक्रम में कार्यरत सभी अधिकारियों उनके कर्मचारियों और श्रमिकों को इलाके को किसी भी भूमि में प्रवेश करने और सर्वेक्षण करने तथा उस धारा द्वारा अपेक्षित अथवा अनुमत: अन्य सभी कार्यों को करने के लिए सहर्ष प्राधिकार देते हैं।

4. कोई भी हितवद्ध व्यक्ति जिसे उक्त परिक्षेत्र में कथित भूमि के अर्जन पर कोई आपत्ति हो तो वह इस अधिसूचना के प्रकाशित होने के तीस (30) दिन की अवधि के भीतर लिखित रूप में भू-अर्जन समाहर्ता लोक निर्माण विभाग, विन्टर फ़िल्ड, शिमला-3 के समक्ष अपनी आपत्ति दायर कर सकता है।

विस्तृत विवरणी

जिला	तहसील	गांव	खसरा नं०	क्षेत्र बीघा	बिस्वा
विलासपुर	घुमारवीं	भवाना	77/76	12	12
			122/95	0	8
			124/95	3	2
क़िता			3	16	2

शिमला-2, 18 फरवरी, 1998

संख्या पी० बी० डब्ल्यू० बी० ए० (7) 1-10/98.—यतः हिमाचल प्रदेश के राज्यपाल को यह प्रतीत होता है कि हिमाचल प्रदेश सरकार को सरकारी व्यय पर सार्वजनिक प्रयोजन हेतु नामतः गांव कोहला, तहसील शाहपुर, जिला कांगड़ा में रेत सलोल सड़क कि० मी० 0/0 से 0/8 तक सड़क के निर्माण हेतु भूमि अर्जित करनी अपेक्षित है, अतएव एतद्द्वारा यह अधिसूचित किया जाता है कि उक्त परिक्षेत्र में जैसा कि निम्न विवरणी में निर्दिष्ट किया गया है, उपरोक्त प्रयोजन के लिए भूमि का अर्जन अपेक्षित है।

2. यह अधिसूचना ऐसे सभी व्यक्तियों को जो इससे सम्बन्धित हो सकते हैं, की जानकारी के लिए भूमि अर्जन अधिनियम, 1894 की धारा 4 के उपबन्धों के अन्तर्गत जारी की जाती है।

3. पूर्वोक्त धारा द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए, राज्यपाल, हिमाचल प्रदेश इस समय इस उपक्रम में कार्यरत सभी अधिकारियों, उनके कर्मचारियों और श्रमिकों को इलाके की किसी भी भूमि में प्रवेश करने और सर्वेक्षण करने तथा उस धारा द्वारा अपेक्षित अथवा अनुमत: अन्य सभी कार्यों को करने के लिए सहर्ष प्राधिकार देते हैं।

4. कोई भी हितवद्ध व्यक्ति जिसे उक्त परिक्षेत्र में कथित भूमि के अर्जन पर कोई आपत्ति हो तो वह इस अधिसूचना के प्रकाशित होने के तीस (30) दिन की अवधि के भीतर लिखित रूप में भू-अर्जन समाहर्ता लोक निर्माण विभाग, कांगड़ा के समक्ष अपनी आपत्ति दायर कर सकता है।

विवरणी

जिला	तहसील	गांव	खसरा नं०	क्षेत्र (हेक्टेयरों में)
1	2	3	4	5
कांगड़ा	शाहपुर	कोहला	95/1	0 02 96

1	2	3	4	5
			104/1	0 04 80
			107/1	0 02 37
		किल्ला	3	0 10 13

*गांव बासा (नगरोटा सूरियां) तहसील ज्वाली, जिला कांगड़ा में देहरा ज्वाली सड़क के निर्माण हेतु।

संख्या लो० नि० (ख) 7(1)88/90.

शिमला-2, 18 फरवरी, 1998.

कांगड़ा	ज्वाली	बासा नगरोटा सूरियां		
			273/1	0 00 90
			274/1	0 10 27
			275	0 09 11
			276/1	0 03 03
			280/1	0 04 40
			281	0 01 26
			282	0 08 41
			283/1	0 09 90
			284/1	0 12 16
			423/1	0 04 00
			625/1	0 00 04
			634/1	0 00 42
			635/1	0 01 50
			636/1	0 01 01
			638/1	0 02 06
			639/1	0 02 24
			640	0 12 46
			646/1	0 00 70
			649/1	0 00 35
			651/1	0 00 66
			655/1	0 00 87
			656	0 01 05
			657/1	0 00 60
			658	0 02 70
			661	0 02 53
			662/1	0 01 18
			663/1	0 00 48
			664/1	0 00 07
			683/1	0 00 04
			684/1	0 00 12
			685/1	0 00 18
			686/1	0 00 36
			688/1	0 00 40
			689	0 00 20
			690	0 00 56

1	2	3	4	5
			697	0 00 33
			698	0 00 32
			699/1	0 00 24
			744/1	0 00 15
			760/1	0 00 63
			761/1	0 00 49
			762/1	0 00 18
			763/1	0 00 20
			770/1	0 00 45
			771/1	0 00 40
			772/1	0 00 40
			773/1	0 00 46
			774/1	0 00 46
			785/1	0 00 25
			786/1	0 00 58
			787/1	0 00 86
			810	0 04 81
			814	0 00 14
			816	0 00 18
			817	0 01 20
			818	0 01 05
			819	0 00 70
			820	0 01 75
			832	0 00 90
			833	0 00 21
			836	0 00 33
			837	0 01 43
			839/1	0 00 32
			840	0 01 17
			841	0 00 66
			842/1	0 00 10
			843	0 00 12
			890	0 00 65
			891	0 00 66
			896	0 00 96
			897	0 00 36
			900/1	0 00 07
			901	0 00 66
			902	0 01 12
			903/1	0 00 22
			904/1	0 00 15
			906	0 00 21
			907	0 00 55
			908	0 00 96

1	2	3	4	5
			909	0 00 57
			910	0 00 17
			911/1	0 00 23
			912	0 01 56
			913	0 01 80
			915/1	0 00 26
		कित्ता ..	85	1 28 88

आदेश द्वारा;
हस्ताक्षरित/-
सचिव।

शिमला-2, 19 फरवरी, 1998

सं० लो० नि० (ख) (7) (1) 174/97.—यतः हिमाचल प्रदेश के राज्यपाल को यह प्रतीत होता है कि हिमाचल प्रदेश सरकार को सरकारी व्यय पर सार्वजनिक प्रयोजन हेतु नामतः गांव सलनू, तहसील सदर, जिला बिलासपुर में कन्दरौर सलनू सड़क के निमाणं हेतु भूमि अर्जित करनी अपेक्षित है, अतएव एतद्द्वारा यह अधिसूचित किया जाता है कि उक्त परिक्षेत्र में जैसा कि निम्न विवरणी में निदिष्ट किया गया है, उपरोक्त प्रयोजन के लिए भूमि का अर्जन अपेक्षित है।

2. यह अधिसूचना ऐसे सभी व्यक्तियों को, जो इससे सम्बन्धित हो सकते हैं, की जानकारी के लिए भूमि अर्जन अधिनियम, 1894 की धारा 4 के उपबन्धों के अन्तर्गत जारी की जाती है।

3. पूर्वोक्त धारा द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए राज्यपाल, हिमाचल प्रदेश इस समय इस उपक्रम में कार्यरत सभी अधिकारियों, उनके कर्मचारियों और श्रमिकों को इलाके की किसी भी भूमि में प्रवेश करने और सर्वेक्षण करने तथा उस धारा द्वारा अपेक्षित अथवा अनुमतः अन्य सभी कार्यों को करने के लिए सहर्ष प्राधिकार देते हैं।

4. कोई भी हितवद्ध व्यक्ति जिसे उक्त परिक्षेत्र में कथित भूमि के अर्जन पर कोई आपत्ति हो तो वह इस अधिसूचना के प्रकाशित होने के तीस (30) दिन की अवधि के भीतर लिखित रूप में भू-अर्जन समाहर्ता लोक निर्माण विभाग, बिन्दर फिट्ठ, शिमला-3, हिमाचल प्रदेश के समक्ष अपनी आपत्ति दायर कर सकता है।

विवरणी

जिला	तहसील	गांव	खसरा नं०	क्षेत्र (बीघों में)	
1	2	3	4	5	6
बिलासपुर	सदर	सलनू	45	16	7
			371	0	2
			383	3	3
			384	4	3
			385	1	9

1	2	3	4	5	6
			393	0	8
			396	0	6
			698/485	5	9
			699/485	2	0
			486	5	17
			487	2	7
			488	26	1
			489	9	13
			490	3	7
			491	9	14
			492	1	10
			493	0	11
			494	4	1
			630/508	8	16
			632/508	2	10
			641/508	4	0
			645/508	2	17
		किता ..	22	114	11

शिमला-2, 19 फरवरी, 1998

संख्या लो० नि० (ख०) 7(1) 220/97.—यतः हिमाचल प्रदेश के राज्यपाल को यह प्रतीत होता है कि हिमाचल प्रदेश सरकार को सरकारी व्यय पर सार्वजनिक प्रयोजन हेतु नामतः गांव बांजन, तहसील अर्की, जिला सोलन में बांजन चनोग सड़क के निर्माण हेतु भूमि अर्जित करनी अपेक्षित है, अतएव एतद् द्वारा यह अधिसूचित किया जाता है कि उक्त परिक्षेत्र में जैसा कि निम्न विवरणी में निर्दिष्ट किया गया है उपरोक्त प्रयोजन के लिए भूमि का अर्जन अपेक्षित है।

2. यह अधिसूचना ऐसे सभी व्यक्तियों को, जो इससे सम्बन्धित हो सकते हैं की जानकारी के लिए भूमि अर्जन अधिनियम, 1894 की धारा 4 के उपबन्धों के अन्तर्गत जारी की जाती है।

3. पूर्वोक्त धारा द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए राज्यपाल, हिमाचल प्रदेश इस समय इस उपक्रम में कार्यरत सभी अधिकारियों, उनके कर्मचारियों और श्रमिकों को इलाके की किसी भी भूमि में प्रवेश करने और सर्वेक्षण करने तथा उस धारा द्वारा अपेक्षित अथवा अनुमतः अन्य सभी कार्यों को करने के लिए सहर्ष प्राधिकार देते हैं।

4. कोई भी हितवद्ध व्यक्ति जिसे उक्त परिक्षेत्र में कथित भूमि के अर्जन पर कोई आपत्ति हो तो वह इस अधिसूचना के प्रकाशित होने के तीस (30) दिन की अवधि के भीतर लिखित रूप में भू-अर्जन समारहर्ता लोक

निर्माण विभाग, सोलन, हिमाचल प्रदेश के समक्ष अपनी आपत्ति दायर कर सकता है।

विस्तृत विवरणी

जिला : सोलन

तहसील : अर्की

गांव	खसरा नं०	क्षेत्र बीघा बिस्वा
बांजन	82	3 13
	85	4 15
किता ..	2	8 8

शुद्धि पत्र

शिमला-2, 19 फरवरी, 1998

संख्या सी०बी० डब्ल्यू-बी० ए० (7) 1-148/97.—इस विभाग द्वारा जारी सम संख्यक अधिसूचना दिनांक 24-10-97 जो गांव क्लोन (242) तहसील चुराह, जिला चम्बा में तीसा हिमगिरि सड़क के निर्माण हेतु अर्जित की जा रही भूमि बारे धारा-4 के अन्तर्गत जारी हो गई है, में पाई गई अशुद्धियों को निम्न प्रकार से पढ़ा जावे:—

गांव क्लोन

आराजी खसरा नं० 110/1 रकबा तादादी 0-4 बीघा के स्थान पर आराजी खसरा नं० 110 रकबा तादादी 0-4 पढ़ा जावे।

आदेश द्वारा;

हस्ताक्षरित/-
सचिव।

आवास विभाग

अधिसूचना

शिमला-171002; 20 फरवरी, 1998

सं० आवास-6(एफ) 7-8/87.—यतः राज्यपाल हिमाचल प्रदेश को यह प्रतीत होता है कि हिमाचल प्रदेश आवास बोर्ड जो कि भू-अर्जन अधिनियम, 1894 की धारा 3 (सी० सी०) के अर्थान्तर्गत, राज्य सरकार के स्वामित्व और नियन्त्रण के अधीन एक निगम है के द्वारा अपने व्यय पर सार्वजनिक प्रयोजन हेतु नामतः मोहाल हरिपुर, तहसील एवं जिला चम्बा, हिमाचल प्रदेश में आवास बस्ती के निर्माण हेतु भूमि अर्जित की जानी अपेक्षित है अतएव एतद द्वारा यह घोषित किया जाता है कि उक्त परिक्षेत्र में जैसा कि निम्न विवरणी में विनिर्दिष्ट किया गया है, उपरोक्त प्रयोजन के लिए भूमि का अर्जन अपेक्षित है।

2. यह अधिसूचना ऐसे सभी व्यक्तियों को जो इससे सम्बन्धित हो सकते हैं, की जानकारी के लिए भू-अर्जन अधिनियम, 1894 की धारा 4 के अन्तर्गत जारी की जाती है।

3. पूर्वोक्त धारा द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करने हुए, राज्याल हिमाचल प्रदेश, इस समय इस उपक्रम में कार्यरत सभी अधिकारियों, उसके कर्मचारियों और श्रमिकों को इलाके की किसी भी भूमि में प्रवेश करने और सर्वेक्षण करने तथा उन धारा द्वारा अपेक्षित या अनुमत अन्य सभी कार्यों को करने के लिए सहर्ष प्राधिकार देते हैं।

4. कोई भी ऐसा हितबद्ध व्यक्ति जिसे उक्त क्षेत्र में कथित भूमि के अर्जन पर कोई आपत्ति हो तो वह इस अधिसूचना के प्रकाशित होने के तीस (30) दिन की अवधि के भीतर लिखित रूप में भू-अर्जन समाहर्ता (एस0 डी0 एम0), चम्बा के समक्ष अपनी आपत्ति दायर कर सकता है।

विवरणी

जिला : चम्बा

तहसील : चम्बा

गांव 1	खसरा नं० 2	क्षेत्र (बीघों में) 3	
महाल हरिपुर	680	0	4
	682	1	0
	694	0	1
	698	0	17
	701	1	13
	702	1	3
	703	0	10
	704	0	5
	705	0	2
	706	3	4
	709	1	5
	710	0	2
	1638/711	3	2
	1640/717	15	18
	718	0	12
	720	0	17
	721	2	16
कुल ..	17	32	10

आदेशानुसार,

रवि डींगरा,
वित्तायुक्त एवं सचिव।

लोक निर्माण विभाग

अधिसूचनाएं

शिमला-2, 24 फरवरी, 1998

संख्या पी0बी0 डब्ल्यू0 ए0 (7) 1-124/97. — यतः हिमाचल प्रदेश के राज्यपाल, को यह प्रतीत होता है कि हिमाचल प्रदेश सरकार को सरकारी व्यय पर सार्वजनिक प्रयोजन हेतु नामत गांव चनोल, तहसील कोटखाई, जिला शिमला में थाना लिंक सड़क निर्माण हेतु भूमि ली जानी अपेक्षित है, अतएव एतद् द्वारा यह घोषित किया जाता है कि नीचे विवरणी में वर्णित भूमि उपर्युक्त प्रयोजन के लिए अपेक्षित है।

2. यह घोषणा भूमि अर्जन अधिनियम, 1894 की धारा 6 के उपबन्धों के अधीन इससे सम्बन्धित सभी व्यक्तियों को सूचना हेतु की जाती है तथा उक्त अधिनियम की धारा 7 के अधीन भूमि अर्जन समाहर्ता लोक निर्माण विभाग, रामपुर बुधैहर को उक्त भूमि अर्जन करने के आदेश लेने का एतद् द्वारा निदेश दिया जाता है।

3. भूमि का रेखांक भू-अर्जन समाहर्ता, लोक निर्माण विभाग, रामपुर बुधैहर के कार्यालय में निरीक्षण किया जा सकता है।

विवरणी

जिला : शिमला

तहसील : कोटखाई

गांव	खसरा नं०	बीघा विस्वा	
1	2	3	4
जनोल	112/1	0	9
	254/111/1	0	7
	252/81/	0	12

कित्ता

..

3

1

8

*गांव कसुम्पटी, सरधीन तथा मैहली, तहसील व जिला शिमला में पंथाघाटी शिव मन्दिर सड़क के निर्माण हेतु।

संख्या पी0 बी0 डब्ल्यू0 बी0 ए0 (7) 1-147/97

शिमला-2, 24 फरवरी, 1998

विवरणी

जिला : शिमला

तहसील : कोटखाई

गांव	खसरा नं०	(बीघा विस्वा)	
कसुम्पटी	542/479/214/1	0	6
	226/1	0	17
कित्ता ..	2	1	3
सरधीन	863/69/3/1	0	13
कित्ता ..	1	0	13
मैहली	1049/20/1	0	4
कित्ता ..	1	0	4

आदेश द्वारा,
हस्ताक्षरित/-
सचिव।

राजस्व विभाग

अधिसूचना

शिमला-2, 24 फरवरी, 1998

सं० रैव-डी (ए०) 2-12/94-सोलन.—राज्यपाल, हिमाचल प्रदेश भू-राजस्व अधिनियम, 1953 (1954 की अधिनियम संख्या 6) की उप धारा 28 की उपधारा 1 के खण्ड (बी) में प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए श्री जगदेव चन्द शर्मा, बी श्रेणी नायब तहसीलदार, तहसील कार्यालय नालागढ़ को उक्त अधिनियम के अन्तर्गत सहायक समाहर्ता, द्वितीय श्रेणी की शक्तियां सहर्ष प्रदान करते हैं, जो कि उनके द्वारा उनके क्षेत्राधिकार की स्थानीय सीमाओं के अन्दर प्रशिक्षण अवधि में कार्यग्रहण तिथि से प्रयोग की जाएंगी।

आदेश द्वारा,

हर्ष गुप्ता,
वित्तायुक्त एवं सचिव।

खाद्य एवं आपूर्ति विभाग

अधिसूचना

शिमला-2, 24 फरवरी, 1998

संख्या 3-162/82-सी० एस०-827-879.—इस कार्यालय द्वारा जारी अधिसूचना संख्या 3-162/82 सी० एस०-151-200, दिनांक 13-1-98 की निरन्तरता में तथा हिमाचल प्रदेश जमाखोरी एवं मुनाफाखोरी निरोधक आदेश, 1977 की धारा 3(1)(ई) के अन्तर्गत प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुये मैं, बी० एस० नैन्टा (भा० प्र० से०), जिला दण्डाधिकारी, सोलन, जिला सोलन उपरोक्त आदेश की अनुसूचि में दर्ज आवश्यक वस्तुओं के परचून भाव को हिमाचल प्रदेश के असाधारण राजपत्र में प्रकाशित होने के एक माह के पश्चात् आगामी दो माह तक लागू रखन क आदेश देता हूं।

हस्ताक्षरित/-
जिला दण्डाधिकारी,
सोलन, जिला सोलन, (हि० प्र०)